औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की पहचान किया जाना

2328. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में उद्योग रहित जिलों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उत्तर प्रदेश के उद्योग-रहित जिलों में उद्योगों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाये गये हैं तथा भविष्य हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(च) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों, विशेषकर उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में कितने सरकार उद्योग कार्य कर रहे हैं, इन उद्योगों में अन्तर्ग्रस्त पूंजी का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) वर्तमान में पिछड़े जिलों का पता लगाने का कार्य वित्त मंत्रालय के पास है।

(ग) से (ङ) "उद्योग रहित जिला' योजना, 1983 के अंतर्गत, जिला उद्योग केंद्र कार्य योजना 1979-80 के अनुसार देश में कुल 93 जिलों को "उद्योग रहित जिलों" के रूप में चुना गया था। ग्यारह जिले अर्थात बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर जालौन, जौनपुर, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और उत्तर काशी जिलों को उत्तर प्रदेश राज्य में "उद्योग रहित जिलों" के रूप में चुना गया था और चार जिलों अर्थात अल्मोड़ा, पिथोरागढ़, देहरादून और नैनीताल को राज्य में विशेष क्षेत्र जिलों के रूप में पहचान की गयी थी।

उद्योग रहित जिला योजना, 1983 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर, जालौन, कानपुर देहात, फतेहपुर, सल्तानपुर, बांदा और हमीरपुर जिलों में सात केंद्र स्वीकृत किये गये थे। योजना के सामाप्त होने से पहले इन सात केंद्रों को केंद्रीय सहायता के रूप में कुल 6 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी, फिर इन्हें विकास केंद्र योजना में बदल दिया गया था। जिसके अधीन जौनपुर जिले में मुंगरा सथारिया के एक केंद्र को स्वीकृत किया गया है जहां 450 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता पहले ही जारी कर दी गई है। "उद्योग रहित जिला" पौड़ी गढ़वाल के पदमपुर शिवराजपुर में भी एक विकास केंद्र स्थापित किया जाना है।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Cement Corporation of India Unit

2329. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Cement Corporation of India's Unit at Kurkunta, Bangalore continues to depend on wet process technology for product, a process which requires high oral consumption;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the above plant requires modernisation;

(d) whether the plant authorities have submitted any modernisation scheme to Government; if so, the details thereof; and

(e) by when the plan/scheme is likely to be approved?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Yes Sir.

(b) Wet process technology was the prevailing technology at that time when the Kurkunta Unit of Cement Corporation of India (CCI) was conceptualised.

(c) to (e) The Company has submitted a draft revival proposal for consideration by the Operating Agency appointed by the BIFR. The proposal, inter-alia, envisages modernisation of Kurkunta Unit also. The recommendations of the Operating Agency, as and when finalised, will be considered by the BIFR, which is a quasi-judicial body.

Memorandum by Industrial entrepreneur

2330. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) number of industrial entrepreneur Memoranda those have been filed and are pending;